CLASS : 12th (Sr. Secondary) **2067/2017**

Series : SS-M/2017

Total No. of Printed Pages : **32** ***SET : A, B, C & D***

MARKING INSTRUCTIONS AND MODEL ANSWERS

SOCIOLOGY

ACADEMIC/OPEN

(Only for Fresh Candidates)

उप-परीक्षक मूल्यांकन निर्देशों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करके उत्तर-पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करें। यदि परीक्षार्थी ने प्रश्न पूर्ण व सही हल किया है तो उसके पूर्ण अंक दें।

General Instructions :

(i) *Examiners are advised to go through the general as well as specific instructions before taking up evaluation of the answer-books.*

(ii) *Instructions given in the marking scheme are to be followed strictly so that there may be uniformity in evaluation.*

(iii) *Mistakes in the answers are to be underlined or encircled.*

(iv) *Examiners need not hesitate in awarding full marks to the examinee if the answer/s is/are absolutely correct.*

(v) *Examiners are requested to ensure that every answer is seriously and honestly gone through before it is awarded mark/s. It will ensure the authenticity as their evaluation and enhance the reputation of the Institution.*

(vi) A question having parts is to be evaluated and awarded partwise.

(vii) If an examinee writes an acceptable answer which is not given in the marking scheme, he or she may be awarded marks only after consultation with the head-examiner.

(viii) If an examinee attempts an extra question, that answer deserving higher award should be retained and the other scored out.

(ix) Word limit wherever prescribed, if violated upto 10%. On both sides, may be ignored. If the violation exceeds 10%, 1 mark may be deducted.

(x) Head-examiners will approve the standard of marking of the examiners under them only after ensuring the non-violation of the instructions given in the marking scheme.

(xi) Head-examiners and examiners are once again requested and advised to ensure the authenticity of their evaluation by going through the answers seriously, sincerely and honestly. The advice, if not headed to, will bring a bad name to them and the Institution.

महत्त्वपूर्ण निर्देश :

(i) अंक-योजना का उद्देश्य मूल्यांकन को अधिकाधिक वस्तुनिष्ठ बनाना है। अंक-योजना में दिए गए उत्तर-बिन्दु अंतिम नहीं हैं। ये सुझावात्मक एवं सांकेतिक हैं। यदि परीक्षार्थी ने इनसे भिन्न, किन्तु उपयुक्त उत्तर दिए हैं, तो उसे उपयुक्त अंक दिए जाएँ।

(ii) शुद्ध, सार्थक एवं सटीक उत्तरों को यथायोग्य अधिमान दिए जाएँ।

(iii) परीक्षार्थी द्वारा अपेक्षा के अनुरूप सही उत्तर लिखने पर उसे पूर्णांक दिए जाएँ।

(iv) वर्तनीगत अशुद्धियों एवं विषयांतर की स्थिति में अधिक अंक देकर प्रोत्साहित न करें।

(v) भाषा-क्षमता एवं अभिव्यक्ति-कौशल पर ध्यान दिया जाए।

(vi) मुख्य-परीक्षकों/उप-परीक्षकों को उत्तर-पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने के लिए केवल Marking Instructions/Guidelines दी जा रही हैं, यदि मूल्यांकन निर्देश में किसी प्रकार की त्रुटि हो, प्रश्न का उत्तर स्पष्ट न हो, मूल्यांकन निर्देश में दिए गए उत्तर से अलग कोई और भी उत्तर सही हो, तो परीक्षक, मुख्य-परीक्षक से विचार-विमर्श करके उस प्रश्न का मूल्यांकन अपने विवेक के अनुसार करें।

1. (i) ईसाई समुदाय 2.3% है।

(ii) सर्वप्रथम प्रश्नावली की बहुत सारी प्रतियाँ तैयार करना ही बड़ी कठिनाई है।

(iii) 1632 भाषायें व बोलियाँ बोली जाती हैं।

(iv) भारतीय संविधान।

(v) बंबई और मद्रास।

(vi) ग्रीन पीस, द रेडक्रास ऐम्नेस्टी इन्टरनेशनल।

(vii) अन्य पिछड़े वर्ग।

(viii) 2011 नई जनगणना का वर्ष है।

(ix) नहीं। यह प्रसिद्ध रेशम मार्ग से जाना जाता है।

(x) नहीं। मुम्बई को कहा जाता है।

(xi) उचित।

(xii) सही।

(xiii) उपनिवेशवाद।

(xiv) सभी।

(xv) पूँजीवादी व्यवस्था पर आधारित था।

(xvi) उचित।

2. **खण्डात्मक संगठन :** जातियों में आपसी उप-विभाजन भी होता है अर्थात जातियों में हमेशा उपजातियाँ होती है और कभी-कभी उपजातियों में भी उपजातियाँ होती हैं। इसे खंडात्मक संगठन कहते हैं।

3. **शिशु मृत्यु-दर :** से अभिप्राय एक हजार जन्में बच्चों में से एक वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले होने वाली शिशु-मृत्यु संख्या से है।

4. **राज्य :** "मैक्स वेबर" ने 'राज्य' को "वैधानिक हिंसा का एकाधिकार" कहा है।

5. **प्रेक्षण :** एक शोधकर्ता की किसी समूह अथवा समुदाय का निरीक्षण कर प्रत्यक्ष भागीदारी द्वारा सूचनायें एकत्र करना है।

6. **साम्प्रदायिकता :** अपने आप में एक ऐसी अभिवृत्ति है जो अपने समूह को ही श्रेष्ठ समूह मानती है और अन्य समूहों को निम्न और अपना विरोधी मानती है।

7. **नगरीकरण :** सामाजिक परिवर्तन की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी समाज में नगरों की संख्या में वृद्धि या उन स्थानों द्वारा नगरीय विशेषताओं को ग्रहण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है।

8. **औद्योगीकरण :** एक वह प्रक्रिया है, जिसमें वस्तुओं का उत्पादन विद्युत् व स्टीम द्वारा संचालित मशीनों द्वारा किया जाता है।

9. **सहभागी लोकतन्त्र :** एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें महत्त्वपूर्ण निर्णय लेने के लिये किसी समुदाय के सदस्य एक साथ भाग लेते हैं।

10. **ग्रामीण लोग :** कृषि कार्यों के अतिरिक्त परिवहन सेवा, व्यवसाय या शिल्प निर्माण जैसे कार्यों को अपनाते जा रहे हैं।

11. **घर परिवार में :** काम आने वाले उपकरण ओवन, टोस्टर, प्रेशरकुकर, वाशिंग मशीन, खाद्य परिसाधक आदि हैं।

12. **साक्षात्कार सर्वेक्षण से :** भिन्न है जैसे साक्षात्कार हमेशा व्यक्तिगत होता है और इसमें कम लोगों को शामिल किया जाता है जबकि सर्वेक्षण में सामान्यतः निर्धारित प्रश्नों को अपेक्षाकृत बड़ी संख्या में लोगों से पूछा जाता है। इसमें प्रश्नावली उत्तरदाता को सौंप दी जाती है।

13. **भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस :** की विशेषज्ञ सभा ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसमें यह घोषणा की गई थी कि भारत एक गणतन्त्र होगा

जहाँ सभी के लिये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित होगा।

14. **लोकतान्त्रिक राजनीति** : हमारा देश एक बहुदलीय प्रणाली वाला देश है। ये सभी दल मिलकर लोकतान्त्रिक व्यवस्था का निर्माण व संचालन करते हैं। संविधान की संरचना तथा राजनैतिक दलों की सक्रियता से जो सम्बन्ध पनपते हैं वो ही लोकतान्त्रिक राजनीति की क्रियाशीलता को सुनिश्चित करते हैं। राजनीतिक दल ही मताधिकार प्रणाली के द्वारा प्रजातन्त्र में लोगों की भावनाओं के अनुरूप ही सरकार का निर्माण करते हैं यही दल जनता की आवाज को सरकार तक पहुँचाते हैं। इतना ही नहीं अपनी आवाज को सरकार तक पहुँचाने के लिये व्यापारी और कर्मचारी तथा किसान अपने-अपने संगठन भी बनाते हैं।

15. **संस्कृतीकरण** : एम० एन० श्रीनिवास कृत एक आवधारणा है जिसमें निम्न जाति या अन्य समूह उच्च जातियों विशेषकर द्विज जाति की जीवन पद्धति, अनुष्ठान, मूल्य, आदर्श, विचारधाराओं का अनुकरण करते हैं। संस्कृतीकरण एक बहुआयामी प्रभावों वाली

प्रक्रिया है। इसके प्रभाव भाषा, साहित्य, विचारधारा, संगीत, नृत्य, नाटक, अनुष्ठान व जीवन पद्धति में देखे जा सकते हैं।

संस्कृतीकरण की प्रक्रिया हिन्दू समाज के अतिरिक्त गैर हिन्दु समूहों व समुदायों में भी देखी जा सकती है। परन्तु यह प्रक्रिया देश के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग ढंग से होती है।

16. **जनसंख्या वृद्धि के मूलभूत चरण :** जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास के समग्र स्तरों से जुड़ी होती है एवम् प्रत्येक समाज विकास से सम्बन्धित जनसंख्या वृद्धि के एक निश्चित स्वरूप का अनुसरण करता है। इसी संदर्भ में जनसंख्या वृद्धि के तीन बुनियादी चरणों का उल्लेख :

पहला चरण है समाज में जनसंख्या वृद्धि का कम होना क्योंकि समाज अल्पविकसित और तकनीकि दृष्टि से पिछड़ा होता है। 'मृत्युदर' और 'जन्मदर' दोनों के ही ऊँचा होने के कारण वृद्धि दरें कम होती हैं।

दूसरे चरण में भी विकसित समाज में जनसंख्या वृद्धि दर नीची रहती है, क्योंकि ऐसे समाज में 'मृत्युदर' और 'जन्मदर' दोनों ही काफी कम हो जाती हैं।

इन दोनों अवस्थाओं के बीच **एक तीसरा** संक्रमणकालीन चरण होता है। जब समाज पिछड़ी अवस्था से उन्नत अवस्था में जाता है, तो जनसंख्या वृद्धि के दरें काफी ऊँची हो जाती हैं।

17. 'स्त्री-पुरुष तुलना' नामक : पुस्तक 1882 में एक महाराष्ट्रीय गृहिणी ताराबाई शिंडे द्वारा लिखी गई थी, जिसमें पुरुष-प्रधान समाज द्वारा अपनाए गये दोहरे मापदण्डों का विरोध किया गया है। इसमें उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार अपने नाजायज नवजात शिशु की हत्या करने पर न्यायालय द्वारा एक जवान ब्राह्मण विधवा को मृत्युदण्ड दिया गया था। इसमें दोहरा मापदण्ड यह अपनाया गया कि जिस पुरुष का वह बच्चा था उसका पता लगाने अथवा उसे दण्ड देने का कोई प्रयास नहीं किया गया था। इस पुस्तक में यह भी दर्शाने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार घर में पत्नी के साथ दासी जैसा व्यवहार किया जाता है।

18. हरित क्रान्ति से ग्रामीण क्षेत्र : स्वातंत्र्योत्तर काल में जहाँ हरित क्रान्ति लागू हुई वहाँ सामाजिक सम्बन्धों की प्रकृति में अनेक प्रभावशाली रूपांतरण हुए। जो निम्न प्रकार से हैं :

(i) गहन कृषि के कारण कृषि मजदूरों की बढ़ोत्तरी।

(ii) भुगतान में सामान के स्थान पर नगद भुगतान।

(iii) 'मुक्त' दिहाड़ी मजदूरी वर्ग का उदय।

(iv) पारम्परिक बंधनों में शिथिलता अथवा भूस्वामी एवं किसान या कृषि मजदूरों के मध्य पुश्तैनी सम्बन्धों में कमी होना।

19. नियोजित विकास के कार्यक्रमों : में निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान केन्द्रित किया गया :

(i) कृषिकीय सुधारों के साथ औद्योगीकरण को शामिल किया गया।

(ii) पैदावार का कम होना।

(iii) आयातित अनाज पर निर्भरता और ग्रामीण जनसंख्या के एक बड़े भाग में गरीबी का होना।

(iv) भूमि सुधार कानूनों की शृंखला को राष्ट्रीय स्तर के साथ-साथ राज्य पर भी लागू करना आदि केन्द्र बिन्दुओं पर ध्यान केन्द्रित किया गया।

1. (i) 1860 के दशक में।

(ii) व्यवसाय तथा प्रस्थिति के आधार पर।

(iii) औद्योगीकरण व नगरीकरण।

(iv) 50% से अधिक लोग स्वरोजगारी हैं।

(v) इसमें बहुत ज्यादा लोगों को शामिल नहीं किया जा सकता।

(vi) बहुत लम्बे समय से काम कर रहे बदली कामगार जिन्हें स्थाई पद और सुरक्षा से वंचित रखा जाता है।

(vii) भार रहित अर्थव्यवस्था।

(viii) सर्वेक्षण प्रणाली।

(ix) हाँ।

(x) नहीं। प्राचीन संस्थान है।

(xi) सही।

(xii) आवश्यक नहीं है अर्थात गलत।

(xiii) अमेरिका ने।

(xiv) स्ववाचक व आत्मवाचक दोनों।

(xv) द्विज जाति का अनुकरण करती है।

(xvi) 11.7%

2. जाति की विशेषता :

(i) जाति जन्म से निर्धारित होती है।

(ii) खण्डात्मक संगठन

(iii) खानपान व सामाजिक सहवास के लिये प्रतिबन्ध आदि शीर्षक में 25 से 30 शब्द अवश्य लिखें।

3. मातृ मृत्यु-दर : एक हजार शिशु जन्मों पर, जन्म देकर मरने वाली स्त्रियों की संख्या मातृ मृत्यु-दर कहलाती है।

4. राष्ट्र : एक ऐसा समुदाय जो अपने आपको एक समुदाय मानता है और अनेक साझा विशिष्टताओं जैसे : सांझी भाषा, भौगोलिक

स्थिति, इतिहास, धर्म, प्रजाति, सजाति, राजनीतिक आकांक्षाओं आदि पर आधारित होता है।

5. **सर्वेक्षण पद्धति** : वह है जिसके द्वारा किसी सामाजिक समूह के किसी पक्ष या घटना के सम्बन्ध में वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है।

6. **अस्पृश्यता** : अछूत मानी जाने वाली वे जातियाँ हैं जिनका जाति अधिक्रम में कोई स्थान नहीं है। वे तो इस व्यवस्था से बाहर हैं।

7. **भूमंडलीकरण** : "आज सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक सम्बन्धों में दुनियाँ की आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। यही भूमंडलीकरण है।"

8. **लोकतन्त्र** : सभी के लिये राजनीतिक, आर्थिक स्वतन्त्रता तथा सामाजिक न्याय है।

9. **जनजाति** : एक सामाजिक समूह जिसमें कई परिवार, वंशज शामिल हों और जो नातेदारी सजातीयता, सामान्य इतिहास अथवा प्रादेशिक राजनीतिक संगठन के साझे सम्बन्धों पर आधारित हो।

10. **आदिवासी आन्दोलनों :** की सर्वाधिक उपलब्धि झारखण्ड और छत्तीसगढ़ के लिये अलग राज्य का दर्जा प्राप्त करना है।

11. **जमींदार व्यवस्था :** इसके अन्तर्गत जमींदार को ही भूमि का स्वामी माना जाता था तथा भूमि सम्बन्धी सभी अधिकार भी उसी के हाथ में होते थे।

12. **सार्वजनिक स्थान :** खुला मैदान, पैदल पटरी, आवासीय बस्तियों में खाली पड़े भूखंड, सार्वजनिक कार्यालयों के बाहर खाली जगह आदि।

13. **जनसम्पर्क और जनसंचार :** के साधन अब ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के समक्ष नगरीय जीवन शैली और उपभोग के स्वरूपों की तस्वीरें पेशकर रहें हैं। परिणाम स्वरूप ग्रामीण उपभोक्ता भी तीव्रता से बाजार के साथ जुड़ते जा रहे हैं। जिससे ग्रामीण तथा नगरीय अन्तर कम हो रहा है।

14. लोकतन्त्र को मजबूत बनाने वाले मुख्य कारक : भारत दुनियाँ का सबसे बड़ा लोकतान्त्रिक देश है यहाँ बहु सांस्कृतिक विविधता है। वैयक्तिक अध्ययन और विश्लेषण यह दर्शाते हैं कि बहु सांस्कृतिक राज्य व्यवस्थाओं में स्थायी सहनशील लोकतन्त्रों की स्थापना की जा सकती है। विविध समूहों के सांस्कृतिक अपवर्जन को खत्म करने और बहुविध तथा पूरक पहचानों का निर्माण करने के लिये स्पष्ट प्रयासों की आवश्यकता है। हाल ही में जो साम्प्रदायिक घटनाएँ हुई है उनके भविष्य में सामाजिक मेल मिलाप की भावनाओं के प्रति गहरी चिन्ताएँ खड़ी होती हैं।

इन सभी खतरों व चिन्ताओं से बचने के लिये अपने लोकतन्त्र को मजबूत बनाने वाले कारकों की ओर ध्यान देना होगा –

(i) नागरिक अपने देश तथा अपनी अन्य सांस्कृतिक पहचानों के साथ तादात्म्य स्थापित करें।

(ii) साझी संस्थाओं में अपना विश्वास बनाये रखें।

(iii) लोकतान्त्रिक राजनीति में सक्रिय भागेदारी।

15. **'वर्ण' और 'जाति' में सम्बन्ध :** वास्तविक सामाजिक स्थिति में वर्ण और जाति स्पष्ट तथा एक दूसरे से सम्बन्धित हैं। सामान्य व्याख्या के अनुसार वर्ण को एक अखिल भारतीय सामूहिक वर्गीकरण के रूप में समझा जा सकता है। वहीं जाति को स्थानीय उपवर्गीकरण के रूप में समझा जा सकता है। यदि चारों वर्गों का वर्गीकरण पूरे भारत में समान है तो जाति अधिक्रम क्षेत्रीय है। देश के सभी भागों में ब्राह्मणों और अस्पृश्य लोगों की स्थितियों से वर्ण का सम्बन्ध सब लोग मानते हैं। ब्राह्मण सबसे ऊँचे और अस्पृश्य सबसे नीचे वर्ण में हैं। ब्राह्मण और अस्पृश्य लोगों के बीच में भी जितनी जातियाँ हैं वे सभी वर्ण के दृष्टिकोण से अपनी-अपनी सामाजिक स्थितियों का दावा करती हैं। जिससे जाति और वर्ण के आपसी सम्बन्धों की जानकारी मिलती है।

16. **सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आन्दोलन में अन्तर :**

(i) सामाजिक परिवर्तन एक निरन्तर गतिमान प्रक्रिया है। यह बदलाव समाज की पहले और बाद की स्थिति को दर्शाता है।

जबकि सामाजिक आन्दोलन कुछ विशेष उद्देश्यों को लेकर चलाये जाते हैं। सामाजिक आन्दोलन सामान्यतः निरन्तर तथा लम्बे काल तक चलते हैं।

(ii) सामाजिक परिवर्तन की वृहद ऐतिहासिक प्रक्रियाएँ असंख्य व्यक्तियों तथा सामूहिक गतिविधियों का परिणाम होती हैं। जबकि सामाजिक आन्दोलन किसी विशिष्ट उद्देश्य की ओर निर्देशित होते हैं।

17. औद्योगीकरण : कुछ एक स्थानों पर जबरदस्त समानता लाता है। उदाहरण स्वरूप रेलगाड़ियों, बसों और साइबर कैफे में जातीय भेदभाव के महत्त्व का न होना। दूसरी तरफ भेदभाव के पुराने स्वरूपों को नए कारखानों और कार्यस्थलों में अभी भी देखा जा सकता है। हालांकि, इस संसार में सामाजिक असमानताएँ कम हो रही हैं लेकिन आर्थिक असमानतायें पैदा हो रही हैं। बहुधा-सामाजिक और आय सम्बन्धी असमानता परस्पर आच्छादित हो जाती है। उदाहरण के लिये अच्छे वेतन वाले व्यवसायों जैसे - मैडिसन, कानून अथवा पत्रकारिता में उच्च जाति के लोगों का

वर्चस्व आज भी बना हुआ है। महिलाएँ समान कार्य के लिये कम वेतन पाती हैं।

18. मतदान का अधिकार : सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भारतीय संविधान द्वारा दिए गये प्रमुख अधिकारों में से एक है। इसका अर्थ यह है कि हम स्वयं अपने द्वारा चुने हुये प्रतिनिधियों के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा शासित नहीं हो सकते। यह अधिकार औपनिवेशिक शासन के दिनों से मौलिक रूप से भिन्न है। हालांकि ब्रिटेन में भी सभी को मतदान का अधिकार नहीं था। मतदान का अधिकार संपत्ति के स्वामियों तक ही सीमित था। सन् 1839 में 12-50 लाख लोगों ने जन चार्टर पर हस्ताक्षर करके संपत्तिहीन होने पर भी चुनाव में खड़े होने के अधिकार की माँग की। सन् 1842 में उक्त आन्दोलन ने 325000 हस्ताक्षर एकत्रित किये। फिर भी प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात् ही सन् 1918 में, 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी पुरुषों, 30 वर्ष से अधिक आयु की विवाहिताओं, गृहस्वामिनियों तथा विश्वविद्यालयी स्नातक महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला।

19. 'बाल-स्त्री' अनुपात में गिरावट आने के कारण :

(i) शैशवास्था में बच्चियों की देखभाल की घोर उपेक्षा के कारण मृत्यु दरों का ऊँचा होना।

(ii) लिंग विशेष जाँच से बालिका शिशुओं की हत्या।

(iii) धार्मिक या सांस्कृतिक अंधविश्वासों के कारण शैशवास्था में ही बच्चियों की हत्या।

(iv) अनेक क्षेत्रों में बालिका हत्या की प्रथाओं का प्रचलन।

(v) आधुनिक चिकित्सा तकनीक जैसे सोनोग्राम का प्रयोग भ्रूण के लिंग का पता लगाने और चयनात्मक आधार पर बालिका भ्रूण को गर्भ में ही नष्ट कर देने के लिये काम में लाया जाने लगा है।

आज भले ही 'प्रधानमन्त्री' के साथ मिल कर राज्य सरकारें ठोस कदम उठा रही हैं फिर भी आमजन को स्वतः ही जागरूक होना होगा।

SET – C

1. (i) स्मिथ ने 'खुले व्यापार' का समर्थन किया।

(ii) एडम स्मिथ की है।

(iii) बड़ी संख्या में एक साथ प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

(iv) भारत।

(v) इसमें लचीलापन होता है।

(vi) द टाइम्स ऑफ इंडिया से है।

(vii) जहाँआरा शाहनवाज ने।

(viii) इस पद्धति के द्वारा कुछ असम्भव व्यवहारों और प्रतिमानों का पता लगाया जा सकता है।

(ix) अनुचित।

(x) अनुचित।

(xi) गलत।

(xii) गलत।

(xiii) तीन (3) भागों में विभाजित किया गया है।

(xiv) सभी।

(xv) 73वें संशोधन के बाद

(xvi) 80.5%

2. **मृत्यु-दर :** एक वर्ष में समग्र जनसंख्या के प्रति एक हजार व्यक्तियों पर मरने वालों की संख्या मृत्यु-दर कहलाती है।

3. **क्षेत्रवाद :** एक खास क्षेत्रीय पहचान के लिये प्रतिबद्ध विचारधारा, जो भौगोलिक क्षेत्र के अलावा, भाषा, सजातीयता आदि अन्य विशेषताओं पर आधारित होती है।

4. **एकीकरण :** सांस्कृतिक जुड़ाव की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सांस्कृतिक विभेद निजी क्षेत्र में चले जाते हैं और एक सामान्य सार्वजनिक संस्कृति सभी समूहों द्वारा अपना ली जाती है।

5. **साक्षात्कार :** सामाजिक शोध की वह पद्धति है जिसके द्वारा साक्षात्कारकर्ता वार्तालाप के द्वारा सूचनादाता से तथ्यों का संकलन करता है।

6. **विनिवेश :** सरकार सार्वजनिक कंपनियों के अपने शेयर्स को निजी क्षेत्र की कंपनियों को बेचने का प्रयास करती है तो उसे विनिवेश कहा जाता है।

7. **वर्ण :** ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र।

8. **प्रेक्षण :** सैट–A में प्रश्न संख्या 5 का उत्तर देखें।

9. **औद्योगीकरण :** यह आधुनिक प्रकार के उद्योगों, कारखानों द्वारा मशीन से बड़ी मात्रा में उत्पादन करने की प्रक्रिया है। यह पिछली दो शताब्दियों से संसार के सामाजिक कार्यों को प्रभावित करने वाली प्रक्रियाओं में सबसे महत्त्वपूर्ण बन गई है।

10. **सुधारवादी सामाजिक आन्दोलन :** वर्तमान सामाजिक तथा राजनीतिक विन्यास को धीमे, प्रगतिशील चरणों द्वारा बदलने का प्रयास करता है।

11. **पंथनिरपेक्षीकरण :** से अभिप्राय उस सामाजिक प्रवृत्ति से है जिसके अन्तर्गत धर्म की प्रधानता और परम्परागत व्यवहारों में धीरे-धीरे तार्किकता और व्यवहारिकता लाने का प्रयास किया जाता है।

12. वर्तमान में भारत में 29 राज्य और 7 केन्द्रीय रूप से प्रशासित प्रदेश हैं। (पाठ्य पुस्तक के आधार पर राज्य 28)

13. 'झारखण्ड' के नये राज्य के रूप में स्थापना के पीछे का इतिहास एक सदी से अधिक का प्रतिरोध है। बिरसा मुंडा नामक आदिवासी ने झारखण्ड के लिये अंग्रेजों के विरुद्ध एक बड़े विद्रोह का नेतृत्व किया था।

14. **पश्चिमीकरण :** डॉ० एम० एन० श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण की अवधारणा को भारतीय समाज में लोकप्रिय बनाया है। उन्होंने अपनी पुस्तक 'भारत में सामाजिक परिवर्तन' में पश्चिमीकरण की परिभाषा देते हुये कहा कि यह भारतीय समाज और संस्कृति, में लगभग 150 वर्षों के ब्रिटिश शासन के परिणाम स्वरूप आए परिवर्तन हैं, जिसमें प्रौद्योगिकी, संस्था, विचार और मूल्य आदि विभिन्न पहलू आते हैं।

आधुनिक भारत में सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन लाने में पश्चिमीकरण की प्रक्रिया की भूमिका महत्त्वपूर्ण रही है। अंग्रेजों ने

अपने लम्बे शासन काल में भारतीय समाज का पाश्चात्य सभ्यता से तो परिचय कराया ही साथ में यहाँ की शासन व्यवस्था को भी अपने ढंग से बदला। आज भारतीय समाज का जो स्वरूप सामने आ रहा है; उसमें काफी सीमा तक पश्चिमी करण की प्रक्रिया का योगदान है।

15. **भूमंडलीकरण और मीडिया :** भूमंडलीकरण के दूरगामी प्रभाव और संचार क्रान्ति के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध हैं। मीडिया के भी हमेशा अनेक अन्तर्राष्ट्रीय आयाम रहे हैं। जैसे कि नए समाचार एकत्र करना और प्राथमिक रूप से पाश्चात्य फिल्मों को दूसरे देशों में बेचना। किन्तु 1970 के दशक तक अधिकांश मीडिया कम्पनियाँ राष्ट्रीय सरकारों के विनियमों का पालन करते हुये, विशिष्ट घरेलू बाजारों में कार्यरत रहीं। मीडिया उद्योग भी अलग-अलग सैक्टरों में विभाजित था। पिछले तीन दशकों में मीडिया उद्योग में अनेक रूपांतरण हुये हैं। राष्ट्रीय बाजारों का स्थान अब तरल भूमंडलीय बाजार ने ले लिया है और नवीन प्रौद्योगिकियों ने मीडिया के विभिन्न रूपों को जो पहले अलग-अलग थे, अब आपस में मिला दिया है।

16. **उदारीकरण :** सन् 1990 के दशक में सरकार ने उदारीकरण की नीति को अपनाया। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये इसे अपनाया गया। निजी कम्पनियाँ, विशेष रूप से विदेशी फर्मों को उन क्षेत्रों में निवेश करने के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिन्हें पहले सरकार के लिये, जैसे दूरसंचार, नागरिक उड्डयन एवम् ऊर्जा आदि आरक्षित रखा जाता था। उद्योगों को खोलने के लिये अनुज्ञप्ति वांछित नहीं है। उदारीकरण के परिणामस्वरूप बहुत सी कम्पनियों को बहुदेशीय कंपनियों ने खरीद लिया है। साथ-ही-साथ कुछ भारतीय कंपनियाँ बहुदेशीय कंपनियाँ बन गई हैं।

उदाहरणार्थ पारले पेय को कोकाकोला द्वारा खरीदा जाना।

17. **जनजातीय आन्दोलन :** देशभर में फैले विभिन्न जनजातीय समूहों के मुद्दे समान हो सकते हैं, लेकिन उनके विभेद भी उतने ही महत्त्वपूर्ण हैं। जनजातीय आन्दोलनों में से कई अधिकांश रूप से मध्य भारत की तथाकथित 'जनजातीय बेल्ट' में स्थित रहे हैं। जैसे - छोटानागपुर, संथाल, हो, अरांव व मुंडा। हम यहाँ

जनजातीय आन्दोलनों के विभिन्न रूपों की चर्चा कर सकते हैं। क्योंकि एक ही क्षेत्र में जनजातीय आन्दोलन के विभिन्न रूप विद्यमान हो सकते हैं। उदाहरण के रूप में झारखण्ड आन्दोलन की चर्चा करें जहाँ जनजातीय आन्दोलन का इतिहास सौ वर्ष पुराना है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने राज्यों के निर्माण की जो प्रक्रिया प्रारंभ की, उसने इस क्षेत्र में (पूर्वोत्तर में) अशांति ही पैदा की। एक मुख्य मुद्दा जो देश के विभिन्न भागों के जनजातीय आन्दोलनों को जोड़ता है, वह है जनजातीय लोगों का वन-भूमि से विस्थापन।

18. **जाति व्यवस्था की विशेषतायें :** जाति व्यवस्था निम्न विशेषताओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती हैं - अर्थात इन शीर्षकों पर थोड़ा-थोड़ा विवेचन कीजिए।

(i) खण्डात्मक विभाजन

(ii) संस्तरण

(iii) भोजन व सामाजिक सहवास पर प्रतिबन्ध

(iv) बिना रोक टोक के व्यवसाय के चुनाव का अभाव।

(v) विवाह सम्बन्धी प्रतिबन्ध।

19. अनुसूचित जातियों व जनजातियों का हित :

पुराने और वर्तमान जातीय भेदभाव को दूर करने और उससे हुई क्षति की पूर्ति करने के लिये राज्य की ओर से कुछ महत्त्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं। इसके अंतर्गत, सार्वजनिक जीवन के विभिन्न पक्षों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सदस्यों के लिये कुछ स्थान अलग से निर्धारित कर दिये जाते हैं। इन आरक्षणों में अनेक किस्म के आरक्षण शामिल हैं जैसे - राज्य और केन्द्रीय विधान-मंडलों में सीटों का आरक्षण, सभी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों के अन्तर्गत सरकारी सेवा में नौकरियों का आरक्षण, शैक्षिक संस्थाओं में सीटों का आरक्षण।

आरक्षणों के अतिरिक्त, और भी बहुत से ऐसे कानून हैं जो अस्पृश्यता को खत्म करने, रोकने अथवा दण्ड देने के लिये बनाये गये हैं।

1. (i) चार भाषायी परिवारों में बाँटा गया है।

(ii) भारत का है।

(iii) 1828 में।

(iv) परियोजन कार्य।

(v) पंडित जवाहर लाल नेहरू।

(vi) सर्वेक्षण पद्धति।

(vii) पारराष्ट्रीय, भाररहित अर्थव्यवस्था आदि।

(viii) ज्योतिबा फुले ने।

(ix) सत्य।

(x) अनुचित।

(xi) सत्य।

(xii) गलत, साक्षात्कार कहलाता है।

(xiii) भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है।

(xiv) ज्योतिबा फुले ने।

(xv) पूँजीवाद कहलाता है।

(xvi) सभी।

2. स्त्री-पुरुष अनुपात : किसी स्थान पर 1,000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या ही स्त्री-पुरुष अनुपात कहलाता है।

3. मूल परिवार : में पति-पत्नी और इनके अविवाहित बच्चे एक ही छत के नीचे रहते हैं। इसे दो पीढ़ी परिवार कहना भी उचित होगा।

4. **सामाजिक बहिष्कार :** वह तौर-तरीके हैं जिनके जरिये किसी व्यक्ति या समूह को समाज में पूरी तरह घुलने मिलने से रोका जाता है।

5. **संविदा खेती :** बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ कुछ विशेष प्रकार की फसलों के उत्पादन के लिये किसानों से संविदा करती हैं। विदेशी कम्पनियाँ कच्चे माल को प्रसंस्करित कर निर्यात करती है।

6. **आर्थिक सुधार :** अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के तहत जब भारतीय व्यापार को नियमित करने वाले नियमों और वित्तीय नियमनों को हटा दिया जाता है तो इन उपायों को आर्थिक सुधार कहा जाता है।

7. **संविधान :** एक लिखित दस्तावेज है जिससे किसी राष्ट्र के सिद्धान्तों का निर्माण होता है। भारतीय संविधान भारत का मूल के मानदंड है।

8. **उपकरण :** (LPG) गैस, वाशिंग मशीन, प्रेशरकुकर, खाद्य परिसाधक और ग्राइंडर आदि ने वास्तव में घर के काम को आसान बना दिया है।

9. **राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार :** सरकार ने हाल ही में ग्रामीण इलाकों में भूख और भुखमरी की समस्या के समाधान के लिये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नामक एक कानून बनाया है।

10. **लेस-एज़-फेयर :** ऐसा बाजार जो किसी भी प्रकार की राष्ट्रीय या अन्य रोकथाम अथवा हस्तक्षेप से मुक्त हो, अर्थात 'बाजार को अकेला छोड़ दिया जाए।' 'स्मिथ'

11. सार्वजनिक स्थानों : का उपयोग कई तरह के छोटे-छोटे काम धंधों में करते हैं। जैसे, सड़क के किनारे की खाली जगह में छिटपुट सामान बेचने, वाहन खड़े करने, विवाह या धार्मिक समारोहों के लिये अथवा सार्वजनिक बैठकों के लिये करते हैं।

12. राज्य की : "राज्य एक ऐसा निकाय होता है जो एक विशेष क्षेत्र में विधिसम्मत एकाधिकार का सफलतापूर्ण दावा करता है।" (मैक्स वेबर)

13. अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग : प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग काका कालेलकर और दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग बी०पी० मंडल की अध्यक्षता में गठित किया गया।

14. झारखंड आन्दोलन : लगभग सात दशक पुराना है। सन् 2000 में दक्षिण बिहार से काट कर बनाया गया झारखंड एक नवनिर्मित राज्य है। झारखंड के लिये करिश्माई नेता बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के विरुद्ध एक बडे विद्रोह का नेतृत्व किया। उन्होंने हिन्दू तथा ईसाई धर्म का घोर विरोध भी किया। उन्होंने जनजातीय प्रथाओं तथा सांस्कृतिक व्यवहारों के बारे में लिखा और उनके बारे में जानकारी प्रदान की। इससे झारखंडियों को संगठित, संजातीय चेतना तथा सामझी पहचान बनाने में सहायता मिली।

15. स्त्री-पुरुष अनुपात : नई जनगणना 2011 के अनुसार हमारे देश में 1000 पुरुषों के पीछे 940 महिलाएँ हैं। जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि आज भी स्त्री-पुरुष अनुपात में गिरावट दर्ज की जा रही है। इसके लिये निम्न कारकों को उत्तरदायी माना जा सकता है।

बाल-विवाह, लड़कियों की अपेक्षाकृत उपेक्षा, पौष्टिक भोजन की कमी, प्रसव सम्बन्धी सुविधाओं का अभाव, कन्याओं की भ्रूण हत्या, बच्चे पैदा करने के लिये केवल स्त्रियों का ही जोखिम उठाना आदि।

16. **भूमंडलीकरण :** 1980 के दशक के बाद, भारत ने अपने आर्थिक इतिहास के नये दौर में प्रवेश किया, ये मुख्यतः राज्य स्तरीय विकास से उदारवाद जैसी आर्थिक नीति के परिवर्तन की वजह से हुआ। इस बदलाव से भूमंडलीकरण के युग की शुरूआत हुई। वह दौर जिसमें दुनियाँ पहले से ज्यादा अर्न्तसम्बन्धी है सिर्फ आर्थिक तौर पर ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और राजनीतिक तौर पर भी। भूमंडलीकरण के खास पहलू भी हैं। जैसे - अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं, पूँजी, समाचार और लोगों का संचलन एवम् साथ ही प्रौद्योगिकी और अन्य आधारभूत सुविधाओं का विकास, जो इस संचलन को गति प्रदान करते हैं।

17. **चिपको आन्दोलन :** राम चन्द्र गुहा ने अपनी पुस्तक 'अशान्तवन' में चिपको आन्दोलन का विस्तार से वर्णन किया है। यह आन्दोलन पर्यावरणीय आन्दोलन का एक सशक्त उदाहरण है, जिसमें सभी के मिश्रित हित और विचारधाराएँ समाहित की गई है।

    अर्थव्यवस्था, पारिज्यिकीय तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्व की चिन्ताएँ चिपको आन्दोलन के आधार रूप में देखी गई। इसमें उल्लेख है कि किस प्रकार सरकारी जंगल के ठेकेदारों द्वारा वनों के काटने को रोकने के लिये महिलाएँ पेड़ों से चिपक जाती हैं। इस विरोध का कारण एक तो गाँव वासियों को जीवन निर्वहन का प्रश्न दूसरे इसका पर्यावरणीय विनाश के रूप में देखा जाना था। जबकि सरकार की मन्शा इसके विपरीत राजस्व कमाने की थी।

18. **धर्मनिरपेक्षतावाद :** एक ऐसे सिद्धान्त पर आधारित सामाजिक नैतिकता की एक व्यवस्था है जिसमें धर्म के नैतिकता के मानदण्ड तथा व्यवहार के निर्धारण के बिना हस्तक्षेप के, वर्तमान जीवन तथा सामाजिक कल्याण की भावना पर बल दिया जाता है।

धर्मनिरपेक्ष का सर्वाधिक सामान्य प्रयोग 'साम्प्रदायिक' के विलोम रूप में किया जाता है। भारत में धर्मनिरपेक्षता एक मूल धारणा है। यह सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करने पर बल देती है। उदाहरण के लिये धर्मनिरपेक्ष भारतीय राज्य सभी धर्मों के त्यौहारों के अवसर पर सार्वजनिक छुट्टी घोषित करता है।

सभी धर्मों को समान आदर और समानता प्रदान कर भारत ने धर्मनिरपेक्षता की अलग पहचान बनाई है।

19. इस प्रश्न के मूल्यांकन के लिये **Set - A** का उत्तर **18** देखें।

विशेष कथन :

(i) उपरोक्त Model Answers केवल संकेत मात्र हैं। इनके अतिरिक्त भी परीक्षार्थी सही उत्तर लिख सकता है, अनदेखा न करें।

(ii) प्रत्येक प्रश्न-पत्र सेट में प्रश्न संख्या **20** व **21** ***आठ-आठ*** अंकों के हैं जिनका मूल्यांकन उप-परीक्षक स्वविवेक से अथवा मुख्य परीक्षक की सहायता से करेंगे।